Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to release due fund to Maharashtra government as per the GST agreement.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने जो एक खत लिखा है, उस खत की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि जीएसटी के माध्यम से जो कमिटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ हुए थे, उस कमिटमेंट के माध्यम से जीएसटी रेवेन्यू अगर कम होता है तो उसके लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए । आज महाराष्ट्र सरकार को कम से कम 15,558 करोड़ रुपये इस वर्ष का मिलना चाहिए, ताकि जीएसटी का जो एग्रीमेंट है, उस हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को न्याय मिलना चाहिए । दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी के पत्र लिखने के बाद भी महाराष्ट्र की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है । वैसे मैं एलीगेशन नहीं लगाऊँगा, लेकिन मैं विनती करूँगा कि महाराष्ट्र में आज शिव सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलायंस की राज्य सरकार काम कर रही है । केंद्र सरकार का महाराष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, उसे वह कर्तव्य निभाने का काम करना चाहिए । अगर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को लगभग 16 हजार करोड़ रुपये यानी 15, 500 करोड़ रुपया एक वर्ष का नहीं मिलता है, तो उसका डेवलपमेंट के ऊपर बुरा असर हो रहा है । महोदय, मेरी आपके माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से विनती है ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम आपकी बात का समर्थन करते हैं ।

श्री विनायक भाउराव राऊत : धन्यवाद । महोदय, आपके माध्यम से मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि चाहे महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की सरकार न हो, लेकिन लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ काम कर रही है । इसलिए जो भी न्याय हो, वह न्याय राज्य सरकार को मिलना चाहिए । धन्यवाद ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री सप्तगिरी उलाका, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन को श्री विनायक भाउराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।